भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2084
बुधवार, 19 मार्च, 2025 (28 फाल्गुन, 1946 (शक)) को उत्तरार्थ

पीएमबीजेकेएस का प्रचालन करने वाली पीएसीएस

2084 श्री संजय सेठः

क्या **सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) अब तक प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केन्द्रों (पीएमबीजेकेएस) के रूप में अनुमोदित प्राथमिक कृषि सहकारी ऋण समितियों (पीएसीएस) की संख्या कितनी है तथा प्रचालनरत पीएसीएस की कुल संख्या कितनी है;

(ख) उक्त केन्द्रों पर कितने प्रकार की जेनेरिक दवाएँ उपलब्ध हैं और उनसे ग्रामीण समुदायों को क्या लाभ हुआ है;

(ग) उक्त पहल से पीएसीएस द्वारा कितना राजस्व सृजित किया गया है और इससे इन समितियों की वित्तीय संधारणीयता में किस प्रकार योगदान दिया गया है; और

(घ) विशेषकर अल्पसेवित क्षेत्रों में, पीएमबीजेकेएस संचालित करने वाली पीएसीएस की संख्या बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

सहकारिता मंत्री
(श्री अमित शाह)

(क): अब तक देश भर में 2,744 PACS को फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइसेस ब्यूरो ऑफ इंडिया (PMBI), औषध विभाग, भारत सरकार से प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र (PMBJK) स्थापित करने का प्रारम्भिक अनुमोदन प्राप्त हो गया है । प्रारम्भिक अनुमोदन प्राप्त 2,744 PACS में से 785 को राज्य औषधि नियंत्रक से औषधि लाइसेंस जारी हो गए हैं और 716 PACS को PMBI द्वारा स्टोर कोड जारी किया जा चुका है जो प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र के रूप में कार्य करने के लिए तैयार हैं ।

(ख): प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र के रूप में कार्य कर रहे PACS लगभग 2,047 गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक औषधियां और शल्यचिकित्सा की लगभग 300 वस्तुएं प्रदान करते हैं । इन उत्पादों में हृदय संबधी, कैंसर-रोधी, मधुमेह-रोधी, संक्रमण-रोधी, एलर्जी-रोधी, गैस्ट्रो-इंटेस्टाइनल औषधियां, न्यूट्रास्यूटिकल्स, आदि जैसे सभी प्रमुख रोग-समूहों के उपचार प्रदान किए जाते हैं । इन केंद्रों पर ग्रामीण जनता को किफायती दामों पर गुणवत्तापूर्ण

जेनेरिक औषधियां प्रदान की जाती हैं और वे ब्रांडेड विकल्पों की कीमत से 50% से 90% तक सस्ती होती हैं जो इसे ग्रामीण आबादी के लिए सबसे किफायती स्वास्थ्य देखभाल सुविधा बनाती है । इस पहल का लक्ष्य ग्रामीण समुदायों की अनिवार्य औषधियों तक पहुंच में सुधार लाना, स्वास्थ्य देखभाल लागत को घटना और उनके समग्र कल्याण में सुधार लाना है ।

(ग): प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों के रूप में कार्य कर रहे PACS अपनी आय-प्रवाहों का विवधीकरण करने और अपनी वित्तीय संवहनीयता में वृद्धि करने में सक्षम हुए हैं । PMBI द्वारा प्रदत्त सूचना के अनुसार अब तक, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों के रूप में कार्य कर रहे PACS द्वारा PMBI से 4.9 करोड़ रुपये मूल्य की औषधियां खरीदी गई हैं । इस पहल ने PACS की वित्तीय व्यवहार्यता को सशक्त किया है और उन्हें अन्य सहकारी कार्यकलापों में पुनर्निवेश करने, अपने सदस्यों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने और ग्रामीण विकास में अपनी भूमिका को विस्तारित करने में सक्षम बनाया है ।

(घ): विशेष रूप से अल्पसेवित/ग्रामीण और सुदूर क्षेत्रों में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों के रूप में कार्य कर रहे PACS की संख्या में वृद्धि करने के लिए, इस पहल के कार्यान्वयन की प्रभावशाली प्रगति सुनिश्चित करने हेतु राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों एवं PMBI के साथ नियमित बैठकों के माध्यम से समीक्षा की जा रही है । किए जा रहे प्रयासों में आवेदन प्रक्रिया का सरलीकरण, अनुमोदन में शीघ्रता और PACS के स्टाफ के लिए फार्मेसी कार्यों पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन शामिल हैं । इसके अतिरिक्त, ग्रामीण स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच बढ़ाने के लिए राज्य सरकारों को प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र शुरू करने हेतु पात्र PACS की पहचान और सहायता के लिए प्रोत्साहित किया जाता है ।

*****